



संपादकीय

बेपरवाही की रेल सुरक्षा

भारत डोगरा

मुद्दा यह है कि रेल दुर्घटनाओं में जो यात्री घायल होते हैं उनमें से अनेक को दीर्घकालीन इलाज की जरूरत होती है। तुरंत तो इलाज मिल जाता है, पर दीर्घकालीन इलाज उपेक्षित रह जाता है। अनेक अध्ययनों में यह सामने आया है कि कई रेल दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की चोट व क्षति बहुत गंभीर होती है व इसके लिए बार-बार अस्पताल जाना पड़ सकता है। ऐसे घायल व्यक्तियों के दीर्घकालीन इलाज की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए व इसके लिए भी रेलवे को पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था करनी चाहिए। रेल प्रबंधन में सुरक्षा को उच्चतम प्राथमिकता देना आवश्यक है। पिछले एक दशक के औसत को देखें तो भारत में प्रतिवर्ष रेल दुर्घटनाओं में 24,000 व्यक्तियों की मौत होती है, जबकि यूरोपियन यूनियन के सभी देशों को मिलाकर देखें तो भी यह आंकड़ा एक हजार से कम है। रेल सुरक्षा में सुधार की जरूरत को देखते हुए वर्ष 2015-16 में समुचित वित्तीय व्यवस्था हेतु उच्च स्तरीय विमर्श किया गया था। फलस्वरूप पांच वर्ष के लिए 1,54,000 करोड़ रुपए व्यवस्था की गई जिसमें से 1,19,000 करोड़ रुपए 'राष्ट्रीय रेल संरक्षक कोष' पर खर्च होने थे। वर्ष 2017-18 से यह कोष आरंभ हुआ, पर इसके लिए पहले पांच वर्ष में एक लाख करोड़ रुपए की ही व्यवस्था हो सकी, यानि मूल अनुमान से 19,000 करोड़ रुपए कम। फिर भी 20,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की राशि का नियोजन तो अगले पांच वर्ष के लिए ही ही गया था वित्त मंत्री की इस घोषणा का स्वागत भी हुआ था। अब यदि सात वर्ष की स्थिति, 2017-18 से 2023-24 तक, देखें तो पहले पांच वर्ष के वास्तविक खर्च के आंकड़े उपलब्ध हैं व नवीनतम दो वर्षों के संशोधित व वास्तविक बजट अनुमान भी उपलब्ध हैं। इनके अनुसार वास्तविक उपलब्ध 1,40,000 रुपए के स्थान पर 96,000 करोड़ रुपए की रही, यानि 44,000 करोड़ रुपए की कमी रही। इसमें पहले ही हो चुकी 19,000 रुपए की कमी भी जोड़ दें तो 'राष्ट्रीय रेल संरक्षक कोष' में सात वर्षों में 63,000 करोड़ रुपए की कमी रही, यानि प्रति वर्ष 9000 करोड़ रुपए की कमी रही। रेलवे मंत्रालय से जुड़ी संसदीय-समिति ने कहा है कि इस तरह संसाधनों में कमी होते रहने से 'राष्ट्रीय रेल संरक्षक कोष' का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। उधर 'कंट्रोलर व ऑफिटर जनरल' (कैग) ने वर्ष 2022-23 में एक रिपोर्ट में ऐसी विधा सहा उठाए तब उत्तर नहीं हो पाया।

का एक रिपोर्ट में ऐसे ही विचार प्रकट करत हुए कहा है कि रेलवे को अपने आंतरिक स्रोतों से 'राष्ट्रीय रेल संरक्षक कोष' के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए। इसके लिए 'कैग' ने 'राष्ट्रीय रेल संरक्षक कोष' के पहले चार वर्षों का आंकलन करते हुए बताया है कि इन वर्षों में रेलवे को अपने आंतरिक स्रोतों से 'राष्ट्रीय रेल संरक्षक कोष' के लिए मात्र 20,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था, पर रेल मंत्रालय इसमें से मात्र 21 प्रतिशत की आपूर्ति ही कर पाया, जबकि 79 प्रतिशत की आपूर्ति नहीं हो पाई। इसके अतिरिक्त 'कैग' रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि सुरक्षा की उच्चतम प्राथमिकताओं के आधार पर कार्य नहीं हो सका। अतः भविष्य के लिए सही प्राथमिकताओं के आधार पर सुरक्षा कार्य को तेजी से आगे बढ़ाना जरूरी हो गया है।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि रेल दुर्घटनाओं में जा यात्रा घायल होते हैं उनमें से अनेक को दीर्घकालीन इलाज की जरूरत होती है। तुरंत तो इलाज मिल जाता है, पर दीर्घकालीन इलाज उपेक्षित रह जाता है। अनेक अध्ययनों में यह सामने आया है कि कई रेल दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की चोट व क्षति बहुत गंभीर होती है व इसके लिए बार-बार अस्पताल जाना पड़ सकता है। ऐसे घायल व्यक्तियों के दीर्घकालीन इलाज की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए व इसके लिए भी रेलवे को पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था करनी चाहिए। नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि घायल यात्रियों की सही संख्या के अनुमान में भी सुधार की जरूरत है। वर्ष 2021 में लगभग 18,000 रेल दुर्घटनाएं हुईं जिनमें मात्र 1800 व्यक्तियों को घायल दिखाया गया, यानि 10 दुर्घटनाओं में मात्र एक घायल दिखाया गया। इन आंकड़ों में सुधार होने से भी अधिक लोगों को सहायता मिल सकेगी। ऐसा तो कहीं भी नहीं देखा गया है कि दस रेल दुर्घटनाओं में मात्र एक घायल हो। अभी हाल की उड़ीसा दुर्घटना को देखें तो उसमें घायल लोगों की संख्या मृतकों की संख्या से तीन गुणा अधिक है।

सामान्य तौर पर यह माना जा सकता है कि एक रेल दुर्घटना में औसतन दो व्यक्ति तो घायल होते ही हैं। यदि इस हिसाब से देखा जाए तो वर्ष 2021 में 18,000 रेल दुर्घटनाओं में लगभग 36,000 लाख लोग घायल हुए होंगे, जबकि आंकड़ों में केवल 1800 व्यक्ति ही घायल बताए गए हैं। सवाल यह उठता है कि यदि बहुत से घायल लोगों के आंकड़े रिकार्ड में दर्ज ही नहीं होंगे तो उनको सहायता कैसे मिलेगी, जबकि भारत, दक्षिण-अफ्रीका, अमेरिका व तुर्की में हुए अध्ययनों में यह बताया गया है कि रेल दुर्घटनाओं में प्रायः जो चोट लगती है वह बहुत गंभीर होती है और उनमें देर तक इलाज की जरूरत होती है। यानि घायल लोगों के इलाज पर कहीं अप्रिय ध्यान देने की ज़रूरत नहै।

घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने

राज सक्सेन

मोदी के विरोध में विपक्षी एकता की सबसे ज्यादा जल्दी दिल्ली के मुख्य मंत्री केजरीवाल और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को है। कुल मिलाकर रिकॉर्ड यह है कि कांग्रेस के मौन विरोध के दृष्टित भी केजरीवाल 23 जून को बिहार में विपक्षी नेताओं की बैठक में भाग लेने और उसमें दिल्ली प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर-परिरक्षा के विषय में निर्णय को लेकर बहुत आशान्वित हैं। शायद उन्हें निरीश कुमार ने विश्वास दिला दिया है कि वे कांग्रेस को मना लेंगे, और नीतीश कुमार दक्षिण में तमिलनाडु जिसका बिहार, उत्तर भारत और दिल्ली की राजनीति में कोई भी साधारण दखल तक नहीं है, वो किसी भी तरह, अपने खेमे में मोदी विरोध के चलते लाने के पूरे प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए वे उन्हें आमित्र करने के लिए चेन्नई भी जा रहे हैं।

प्रयासों में दक्षिण के किसी राज्य की नीतीश की यह पहली यात्रा होगी जिसमें वे मुख्यमंत्रीस्टालिन से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उन्हें आमंत्रित करेंगे। हालांकि स्टालिन को पूर्व में निमंत्रण भेजा जा चुका है किन्तु नीतीश कुमार कोई भी खाना इस विषय में खाली रखने के मूड में नहीं हैं और वे हर विषयकी नेता से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उसे आमंत्रित कर रहे हैं। इस विषय में यह विशेष उल्लेखनीय है कि नीतीश कुमार की बिहार में स्वयं में जनता के बीच कोई खास अच्छी स्थिति नहीं है। उनसे अधिक तो आरेडी के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की है जिसके साथ मिलकर नीतीश कुमार की जेडीयू ने गठबंधन कर सकार बनाइ है। अगर इन दोनों दलों के फिल्हे चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2024 में इन दोनों दलों की स्थिति भाजपा के मुकाबले या यूं कहें

ये इस गठबंधन के लिए बाले राजद का खुद का कारण बन सकता है।)समीकरण यानी 31 बूट पकड़ के दावे के रूपमें चुनावों में राजद 15 प्रतिशत के बीच को 2009 में 19.3 प्रतिशत और 2019 मिले थे। गठबंधन के बह अपने इसवोट बैंक में सफल भीनहीं हो

प यादव समीकरण के रूपमें चुनाव में विहार साथ 22 सीटें जीतकर रक्कार बनाने में अहम

चार सीटें से अधिक जीतने में लोकसभा लड़ना राज वोट शेयर राजद का पाने में तो जीत पाया 2004 के शेयर 10 सीट कम चुनाव में बाद राज हासिल व मामूली संख्या 19.3 प्रति

मिली थी। बिहार में यूपीए45 प्रतिशत
वोटों के साथ 40 में से 29 सीटें
सफल रहा था लेकिन 2009 वें
चुनाव में कांग्रेस से अलग होकर
जनद के लिए भारी पड़ा और उसके
19.3 प्रतिशत पर सिमट गया जबविधि
सहयोगी लोजपा 6.5 प्रतिशत वोटों
सफल रही लेकिन एक भी सीट नहीं
गई। राजदसे अलग होकर कांग्रेस
ने तुलना में दोगुने से भी अधिक वोट
3 प्रतिशत प्राप्त करने के बावजूद एक
जीत पायी। 2014 के लाक्षसभा
भाजपा और जदयू के अलग होने वें
इ के लिए खोये हुए चोट बैंक कं
रने का सुनहरा मौका था लेकिन इसके
वृद्धि के साथ वह 2009 के चुनाव
प्रतिशत से 20.5 प्रतिशत पर ही पहुंच

गीता प्रेस रूपी उजालों पर राजनीति क्यों?

ललित गग्नी

आजादी के अमृतकाल में स्व-संस्कृति, स्व-पहचान एवं स्व-धरातल को सुदृढ़ता देने के अनेक अनूठे उपक्रम प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकार में हो रहे हैं, उन्हीं में एक है भारत सरकार द्वारा एक करोड़ का गांधी शांति पुरस्कार सौ साल से सनातन संस्कृति की संवाहक रही गीता प्रेस, गोरखपुर देने की घोषणा। 1800 पुस्तकों की अब तक 92 करोड़ से अधिक प्रतियां प्रकाशित करने वाले गीता प्रेस को इस पुरस्कार के लिये चुना जाना एक सराहनीय एवं सूझबूझभरा उपक्रम है। यह सम्मान मानवता के सामूहिक उत्थान, धर्म-संस्कृति के प्रचार-प्रसार, अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। लेकिन विडम्बना है कि ऐसे मानवतावादी उपक्रमों को भी राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देने से राजनीतिक दलों और नेताओं को कितना फायदा या नुकसान होता है यह अलग बात है लेकिन सही बात तो यह है कि ऐसे विवादों का खमियाजा देश को जरूर उठाना पड़ता है।

ऐसा ही ताजा विवादित बयान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पुरस्कार को लेकर दिया है। रमेश ने कहा कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देना गोडसे और सावरकर को सम्मान देने जैसा है। निश्चित ही यह तो उजालों पर कालिख पोतने के प्रयास है। ऐसे प्रयास अंधेरे साथों से प्यार करने वाले लोग ही कर सकते हैं। ऐसे लोगों की आखों में किरणें आंज दी जायेतो भी वे यथार्थ को नहीं दे सकते। ऐसे राजनीतिक लोग आकाश में पैबंद लगाना चाहते हैं और साछिद्र नाव पर सवार होकर राजनीति सागर की यात्रा करना चाहते हैं। क्योंकि सब जानते हैं कि गीता प्रेस

प्रातादन सत्तर हजार प्रातया प्रकाशत करने वाले घर-घर में धर्म-संस्कृति-राष्ट्रीयता का दीप जला रहा है। अपनी किताबों के माध्यम से समाज में संस्कार परोसने वाले चरित्र निर्माण का काम भी यह संस्था करने रही है। गीता प्रेस के कामकाज को लेकर आज तक कोई विवाद भी पैदा नहीं हुआ ऐसी संस्था को लेकर जब यह बयान आता है तो यह भी सवाल उठता है कि क्या जयराम रमेश के इस बयान का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है? यहाँ सवाल इसलिए भी क्योंकि जयराम रमेश कांग्रेस के जिम्मेदार नेता हैं और केन्द्र में मंत्री भी रह चुके हैं।

इस तरह के उद्देश्यहीन, उच्छृंखल एवं विध्वंसात्मक बयान सामाजिक समरसता एवं राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर तो करते ही हैं, धर्म, आस्था और संस्कारों को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं को हतोत्साहित भी करते हैं। वैसे भी हर धर्म व उससे जुड़ी संस्थाओं को अपने कामकाज के प्रचार-प्रसार का पूरा हक्क है। गीता प्रेस के बारे में देश के तमाम बड़े नेताओं और धर्मगुरुओं की राय सकारात्मक ही रही है। संस्था ने सकारात्मकता की एक ओर मिसाल पेश करते हुए किसी प्रकार का दान स्वीकार करना

करन क अपन सद्गत क तहत एवं
करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि लेने से
इनकार कर दिया है। साथ ही सरकार ने
अनुरोध किया है कि वह इस राशि का
कहीं और खर्च करे।
गांव जलाने वाला और जलती आग से
बचाने वाला- दोनों एक कैसे हो सकते हैं? गीता प्रेस पर दोषारोपण करने वाला
एवं उसकी जिस तरह से अतिशयोक्तिपूर्ण
तुलना की गयी है, वह आलोचक है
उच्छृंखलता एवं बुद्धिहीनता को दर्शाता
है। गांव जलाने वाले और जलती आग से
बचाने वाले को कोई मन्दवृद्धि व्यक्ति नहीं
एक नहीं मान सकता। फिर गीता प्रेस जैसे
सांस्कृतिक एवं धार्मिक अभियान के साथ
इस विसंगतिपूर्ण आलोचना की सोचना है। इस तरह का
आलोचना राजनीतिक आग्रह, पूर्वगति
एवं दुराग्रह के साथ बुद्धि का
दिवालियापन है। हर मामले का
राजनीतिक रंग में डुबोने की ताक में रहने
राजनेताओं की फितरत-सी बनती जा रही
है। लोकतंत्रीय पद्धति में किसी भी विचारणा
कार्य, निर्णय और जीवनशैली का
आलोचना पर प्रतिबंध नहीं है। किन
आलोचक का यह कर्तव्य है कि वह पूरा
पक्ष को सही रूप में समझकर ही उसे

अपनी आलोचना की छेनी से तराशे। किसी भी तथ्य को गलत रूप में प्रस्तुत कर उसकी आक्षेपात्रक आलोचना करना उचित नहीं है। जिन दलों, लोगों एवं विचारधाराओं का उद्देश्य ही निन्दा करने का हो, उनकी समझ सही कैसे हो? जिसका काम ही किसी अच्छे काम या मन्तव्य को जलील करने का हो, वह सत्य का आईना लेकर क्यों चलेगा? गीता प्रेस के सौ वर्षों का स्वर्णिम दौर एवं संस्कृति-निर्माण के कार्य कोई कार्य का नाजुक घर नहीं है कि आलोचना की बौछार से किरचें-किरचें होकर बिखर जाये। उसने जो संस्कार निर्माण एवं संस्कृति जागरण के सत्य को उजागर किया, वह शताब्दी पहले जितना सत्य था, आज भी उतना ही सत्य है। बल्कि नई परिस्थितियों के साथ उसकी उपयोगिता एवं प्रासारिकता और अधिक बढ़ गयी है। उसकी दूरगमी निगाहों ने अपने युग के पार देखकर जिस सत्य को पकड़ा था, दुर्साहसी कालचक्र उसे किसी भी कोने से खण्डित नहीं कर पाया। उसने तो देश के घर-घर में धर्म की पताका लहराई है, सतातन सत्यों की एक ठोस जमीन दी है, काश! समग्र दृष्टि से विचार करते हुए तथाकथित राजनीतिक लोग इस सिलसिले का सम्मान कर पाते। राजनेताओं को राजनीतिक दलों की कार्यशैली या उनके कार्यक्रमों को लेकर आपति हो सकती है, पर किसी भी निर्विवाद संस्था को बेवजह विवादों में घसीटना अशोभनीय ही कहा जाएगा। यह सही है कि आज के दौर में राजनीतिक दलों व नेताओं की रणनीति बोट बैंक की चिंता और सुखियां बटोरने की आतुरता के ईर्द-गिर्द धूमती है। लेकिन राजनेताओं से यह तो अपेक्षा की जाती है कि वे बयान सोच-समझकर दें। बयान देकर फिर वापस ले लेने से भी जो नुकसान होता है उसकी भरपाई आसान नहीं होती। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे अपने नेताओं के लिये बयानों में संयम बरतने की आचार-संहिता लागू करें। गीता प्रेस की पत्रिका है कल्याण। कल्याण की लोकप्रियता का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि अब तक इस पत्रिका के कई विशेषांकों (पहले अंक) के पाठकों की मांग पर अनेक संस्करण प्रकाशित करने पड़े। चाहे जैसी स्थितियां आईं, कल्याण अपने लक्ष्य, संकल्प व दायित्वबोध के प्रति पूरी तरह सजग रही। भारत बंटवारे का विरोध किया तो जरूरत पड़ने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी मार्गदर्शन किया। भाईजी हनुमान प्रसाद पोद्दार द्वारा कल्याण के रूप में रोपा गया पौधा आज बटवृक्ष बन चुका है। लोगों का धर्म-संस्कृति के क्षेत्र में मार्गदर्शन कर रहा है। भाईजी व गांधीजी के बीच प्रेमपूर्ण संबंध थे। ह्यकल्याणल का पहला अंक 1926 में प्रकाशित हुआ था, इसमें गांधीजी का लेख भी छपा था। भाईजी यह अंक गांधीजी को भेंट करने गए थे। उन्होंने न सिर्फ कल्याण की प्रशंसा की, बल्कि यह आग्रह भी किया था कि कल्याण या गीताप्रेस से प्रकाशित होने वाली किसी पुस्तक में बाहरी विज्ञापन न प्रकाशित किया जाए, इससे कल्याण व पुस्तकों की शुचिता बनी रहेगी। इसका पालन आज भी गीताप्रेस करता है। कल्याण के विभिन्न अंकों में गांधीजी के लेख छपते रहे। आज भी गांधीजी द्वारा लिखा गया पत्र गीताप्रेस में सुरक्षित रखा गया है। गांधीजी के जीवन पर इस पत्रिका का अनूठा प्रभाव रहा है और उन्हीं के नाम पर दिये जाने वाले पुरस्कार के लिये गीता प्रेस से अधिक उपयुक्त पात्र कोई और हो नहीं सकता, यह बात जयराम रमेश को भलीभांति समझ लेनी चाहिए। सस्ती राजनीतिक वाह-वाही के लिये ऐसे बयानों से जयराम रमेश ने अपनी ही पार्टी एवं उसकी ऐतिहासिक विरासत को आहत किया है।

हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं से चिल

अशाक

फिल्म आदिपुरुष भगवान राम पर बना इस फिल्म का देशव्यापी विरोध हो रहा है। कई लोगों को फिल्म के डायलॉग पसंद नहीं आ रहे हैं तो कुछ लोगों को राम बने प्रभास का लुक पसंद नहीं आ रही है। घनी मूँछे, योद्धाओं जैसे शरीर वाले प्रभास में लोगों को भगवान राम की शालीनता खल रही है। आदिपुरुष का विरोध केवल भारत तक सीमित नहीं है। नेपाल में थिएटर मालिकों का कहना है कि जब तक फिल्म के कुछ डायलॉग हटाए नहीं जाते हैं, फिल्म को नेपाल में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि यह फिल्म मूल रामायण का अपमान है, इसमें धार्मिक कथाओं को अलग तरीके से पेश किया गया है। इसे हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ बताया जा रहा है। दरअसल यह फिल्म अपने टीजर के लॉन्च के दिनों से ही विवादों के केंद्र में है। लोग इस फिल्म की कॉस्ट्र्यूम डिजाइन से लेकर संवाद आदायी तक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कई हिन्दू संगठनों ने इस फिल्म पर बैन लगाने की माग की है। फिल्म पर बैन लगाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दायित्व की गई है। याचिका में कहा गया है कि सेंसर बोर्ड की ओर से जारी होने वाले सर्टिफिकेट पर रोक लगा दी जाए।

नेपाल में थिएटर मालिक इस बात से नाराज हैं कि आदिपुरुष में सीता मां को भारत की बेटी बताया गया है। काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर ने मांग की है कि अगर यह लाइन हाईर्ट नहीं जाती है तो फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाए। फिल्म में एक डायलॉग है 'जानकी भारत की बेटी है' सीता मां का मायका, माना जाता है कि जनकपुर में है, जो नेपाल में है। इस डायलॉग को लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रभास इस फिल्म में राम बने हैं। सीता की भूमिका में हैं कृति सैनन और रावण न्यूज हैं गौम राजी उपादान, गौम अपार्टमेंट लक्कड़ी

लकर ट्रॉल हा रह ह। लोगों का सबसे ज्यादा इतराज फिल्म में किरदारों के लुक पर है। ज्यादातर लोगों को फिल्म के किरदारों का कास्टयम पंसद नहीं आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि राम, न तो राम लग रहे हैं, लक्ष्मण का लुक भी मैच नहीं कर रहा है। हनुमान का लुक, रामानंद सागर वाले रामायण से बिलकुल अलग है। लोग, अरुण गोविल के लुक से प्रभास की तुलना कर रहे हैं, जो उनके लुक से बेहद उलट है। यह लोगों को रास नहीं आ रहा है। लोगों का मानना है कि सैफ अली खान का रावण वाला लुक भी बेहद बुरा है। फिल्म के टीजर से लेकर ट्रेलर तक पर बबाल हो रहा है। 2022 से ही इसके फिल्म पर विवाद जारी है। आदिपुरुष फिल्म के निर्माता ओम रातड़, प्रभास, सैफ अली खान समेत 5 लोगों के खिलाफ पहली बार 2022 में यूपी के जौनपुर में केस दर्ज हुआ। फिल्म पर भगवान राम, हनुमान, सीता और रावण के किरदारों का अभद्र चित्रण करने का आरोप लगा। शिकायतकर्ता ने कहा कि फिल्म धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। आदिपुरुष के खिलाफ यहाँ मुईई में भी शिकायत दर्ज हुई है। आरोप है कि यह फिल्म रामचरित मानस के पात्र राम के किरदार को गलत तरीके से दर्शा रही है। हिंदू धर्म समाज ने भी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है। कुछ लोगों को किरदारों के जेनेऊ न पहनने पर भी ऐतराज है। यह फिल्म रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिरी है। कृष्ण देव, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े हैं। उन्होंने फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद कहा कि इस फिल्म के सभी पात्रों को बेमन से चुनाव दिया गया है। सुपरस्टार के भरोसे फिल्म हिट करनाने की कोशिश की गई है। रावण से लेकर हनुमान तक के किरदार ऐसे हैं जो देखने में विदूषक लग रहे हैं। सबके कपड़े, रामायण में वांपिणी किरदारों के स्वरूप से बिलकुल भी नहीं मिलते हैं। दर्शकों का मानना है कि धार्मिक फिल्म को भी तंत्रज्ञा फिल्म बना दिया जाए।

लप्पकाज, छड़ी पत्रकार, राजनातक तोपची, देशदेही वामपर्यायों का गिरोह व विभिन्न माफियाओं समेत भारत विरोधी अराजक तत्वों की गैंग शामिल है जो विविध तरीके से एक-दूसरे के लिए माहौल निर्मित करती है। हिन्दू धर्म विरोध, अपमान के पीछे इनकी वही नफरत है जो इनके विभिन्न कार्यकलापों, बयानों से प्रयाः सामने आती रहती है। हिन्दू धर्म व उसकी व्यवस्था तथा आस्था इनके लिए आसान सा लक्ष्य है, विक्योक्ति इन्हाँ यह बख्खी पता होता है कि हिन्दू अपने धर्म, आस्था के प्रति उतना ढढ़ नहीं है और मुहोड़ जबाब नहीं देता है। साथ ही जो इनके कुकर्त्वों के विरोध में आता है उसे ये अपने 'अधिव्यक्ति' शब्द के जुमले से ढंकने का प्रयास करते हैं। इन फिल्म निमार्ताओं, पटकथा लेखकों, फिल्म निर्देशकों, प्रसारणकाताओं का जो तंत्र होता है वह एक वैचारिकी के घेरे से बधा हुआ व इन्हीं लक्ष्यों को प्रसारित करने के उद्देश्य के लिए ही सिनेमा में आया हुआ है कि- उन्हें हर हाल में 'हिन्दू-हिन्दुत्व' के विरोध, धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने के लिए काम करना है, जिसे वे सिनेमा के माध्यम से आसानी के साथ साध लेते हैं।

चाहे फिल्मों के नाम हों याकि उसके दृश्य, धारावाहिक, कॉमेडी, वेबसीरीज या अन्य दृश्य सामग्री जिन्हें विवादित कहा गया हो तथा जिन पर समाज ने आपत्ति दर्ज करवाकर विरोध किया हो। उन सभी का गहराई से विशेषण करने पर सबके मूल में एक बात ही सामने आती है कि फिल्म निमार्ता, निर्देशकों ने इसके पीछे खास रणनीति के तहत काम किया है। वे जानबूझकर ऐसे नाम, दृश्य, डॉयलॉग इत्यादि उसमें सम्मिलित करते हैं जिससे 'विवाद' की स्थिति निर्मित हो। अब ऐसा करने के पीछे यही है कि प्रथमतः वह विवाद के द्वारा अपनी फिल्म, सीरीज का बिना पैसे के प्रचार प्रसार कर लेते हैं। दूसरा यह कि जिस विशेष उद्देश्य के अन्तर्गत उन्होंने फिल्म, धारावाहिक, वेबसीरीज में 'जानबूझकर विवादित' जीवन-

अल्पसंख्यकों के योजनाओं पर मोदी की टिप्पणी के मायने

गौतम चौध

अभी हाल ही के दिनों में गुजरात की एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि धर्मनिरपेक्षता का सही अभ्यास समृद्धाये के विकास में है। अपने भाषण में उन्होंने यह भी जोड़ा कि कल्याणकारी योजनाओं में बिना किसी भेद-भाव के सभी को समान रूप से शामिल करना और लाभान्वित करना है, चाहे उनकी धार्मिक, जाति और क्षेत्रीय संबद्धता कुछ भी हो। उक्त सभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके अलावा, किसी भी संप्रदाय के व्यक्तियों के हक के वितरण में किसी भी प्रकार के कदाचार या पूर्वाग्रह का उन्मूलन ही धर्मनिरपेक्षता की वास्तविक अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री ने कहा रूप से पूरी हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने की अपनी योजना पर भी स्पष्टिकरण प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि इस प्रयास को पूरा करने के लिए, सरकार ने उन विचित समूहों के लिए सकारात्मक कार्रवाई की दिशा में कार्य योजनाएं तैयार की हैं, जो आर्थिक रूप से धीमी गति से बढ़ रहे हैं। विशेष रूप से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य विचित समूहों की तुलना में मुस्लिम अल्पसंख्यक का आर्थिक विकास थोड़ा कमज़ोर है।

कल्याणकारी योजनाओं में आत्मनिर्भरता और गतिशीलता के लिए आवास, शिक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल और माइक्रो उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता चलाए जा रहे कई योजनाओं की चर्चा की। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से, सरकार ने प्रासंगिक कदम उठाए हैं। इस समाज के लिए नया सर्वेरा, सीखो और कमाओ, नई मजिल, नई रोशनी, हमारी धरोहर, नई डड़ान, गरीब नवाज रोजगार योजना और शादी मुबारक योजना सहित कई योजनाओं को लागू किया है। मुस्लिम विशेष रूप से नई उड़ान पहल के लिए लक्षित समूदाय हैं, जो संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा को प्रभावी ढंग से उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता

चित्रकूट - उन्नाव संदेश

दो के कब्जे से दस लीटर महुआ
शराब व 13 क्वार्टर देशी शराब
बरामद



अखंड भारत संदेश
चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देश पर अवैध शराब निरामण एवं बिक्री की रोकथाम को जारी अधियान में पुलिस ने दो के कब्जे से दस लीटर महुआ शराब व 13 क्वार्टर शराब बरामद की है।

मंगलवार को सरधुआ थाने के देशेगा अनिल कुमार गुप्ता की टीम ने पूलचन्द्र पुत्र नव्य चमर निवासी औद्दाहा के कब्जे से दस लीटर महुआ शराब समेत गिरफतार किया है। उसके खिलाफ थाने में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। टीम में देशेगा अनिल कुमार गुप्ता व सिपाही ललित सोनी सुभम द्विवेदी शामिल रहे।

इसी क्रम में मारुपट्टी धानाधान्य अनिल कुमार की टीम ने राम वर्मा पुत्र नव्य निवासी पुरानी बस्ती थाना मझगंवां जिला सतना मध्य को 13 क्वार्टर देशी शराब समेत गिरफतार किया। उसके खिलाफ थाने में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। टीम में धानाधान्य अनिल कुमार, सिपाही शुभम द्विवेदी शामिल रहे।

पुलिस ने दबोचे तीन वांछित

अखंड भारत संदेश



चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देश पर वांछित/वारंटों की निवासी को जारी अधियान में कब्जे कोतवाल गुलाब त्रिपाठी की अमुवाई में दरोगा रोकथाम मौर्य वांछित टीम ने वांछित शुल्क उपर्युक्त गुप्ता पुत्र छेत्रीलाल व छेत्रीलाल उर्फ मोतीलाल पुत्र स्वर नवदा प्रसाद निवासी गोकलपुरी को गिरफतार किया। टीम में देशेगा रोकथाम मौर्य, सिपाही दिनेश यादव शामिल रहे।

इसी क्रम में प्रामाणी निरीक्षक सरथुआ दीपेन्द्र सिंह की टीम ने पांक्षो एके के वांछित निवास यादव पुत्र बिन्दुलाल यादव निवासी बरावार को गिरफतार किया। टीम में प्रभारी निरीक्षक सरथुआ दीपेन्द्र सिंह, दरोगा सम्बन्धित त्रिपाठी, दीवान अरविंद सोनी, दीवान वैष्णव कुमार, सिपाही लालू यादव शामिल रहे।

क्षेत्र की जनता को न परेशान करें विद्युत कर्मी: विधायक

अखंड भारत संदेश



चित्रकूट। सायांगी पाटी के कब्जे विधायक अनिल प्रधान ने विद्युत की भारी कटौती से परेशान जनता को निजात दिलेने को विद्युत विभाग के नगर कार्यालय का आँचक निरीक्षण किया।

मंगलवार को सदर विधायक अनिल प्रधान ने सरोकर सवाद बजे अधिशासी अधियांता विद्युत नगर कार्यालय का निरीक्षण किया।

निरीक्षण में उन्हें कम्पारी पिरधारीलाल, यजवन क बुलुक कुमार तथा अशोक कुमार और संजय कुमार मौजूद गिरिले। बाकी कटौतीराजी पैरहाजिर रहे। सभी पटलों पर ताला लटका था। उपरित्थि रिकॉर्ड जिस कक्ष में रखा था, वह कक्ष भी बन्द था।

विधायक ने कहा है कि विद्युत व्यवस्था को लेकर क्षेत्र के लोगों को परेशान न किया जाये। पैरहाजिर कर्मियों के खिलाफ कार्रवाही कर उन्हें अवातर करायें।

चुप्पी तोड़ी खुलकर बोलो चैपल में एसपी ने महिलाओं को किया जागरूक, सर्वेय में लगी महिला चैपल



अखंड भारत संदेश
चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक श्रीमती वृन्दा शुक्ला की अध्यक्षता में सीओ मऊ राजकमल की मौजूदी में महिलाओं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विवास का माझौल काम रखने की गरज से जारी मिशन शक्ति अधियान के तहत मानिकुर थाने के सरेया कस्बे के प्राथमिक विद्यालय में महिला चैपल लगाई।

मंगलवार को चैपल में एसपी श्रीमती वृन्दा शुक्ला ने कहा कि अपने प्रति होने वाले छोटे से छोटे अपराध एवं अन्याय के खिलाफ आवाज उठायें। व्यक्तिगत हालात के अनुसार पुलिस हर सम्भव मदद करों। महिलाओं के प्रति होने वाले घेरल, लैंगिक एवं साइबर अपराधों के प्रति सचेत और जागरूक हों। महिलाओं अपराध का शिकायत बनती है तो उस रिक्ति में पुलिस तक आसानी से पहुंचना जा सकता है। इस बाबत महिलाओं व बालिकाओं को जागरूक किया।

उन्होंने पुलिस सेवाओं को बेहतर बनाने को सुनाव भागी। क्षेत्र की महिला सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं से भी महिलाओं को अवगत कराया जिन पर आवश्यक कार्यवाही को जारी रखने से सम्बन्धित को निर्देश दिये। मिशन शक्ति के तहत चल रहे विशेष अधियान के सभी थाना क्षेत्रों में महिला चैपल मालां जा रही हैं। आते ही पुरे सपात में चैपल लाइट जारी हैं। महिला चैपल में प्रभारी निरीक्षक मानिकुर वार प्रताप सिंह, पीआरओ प्रदीप कुमार पाल, चैकी प्रभारी सरेया चन्द्रमणि पाण्डे आदि मौजूद रहे।

शासनादेश का उल्लंघन: सीएमओ पर उठे सवाल

अखंड भारत संदेश
चित्रकूट। सूखे के मुख्य सचिव के शासनादेश के तहत 13 मई 2022 में सम्मेह ग के एसे कम्पचारी जिनका एक ही पटल में तीन वर्ष पूरे हो गए हैं। उनके पटल परिवर्तन के आदेश जारी हुए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा भूषण द्विवेदी ने कम्पचारीयों का पटल बदला तो था, लेकिन कुछ समय बाद पुनः कम्पचारीयों का तबादला तुरने स्थान पर किया जा रहा है। शासन के आदेश की धृजियां उड़ाई जा रही हैं। मंगलवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के फेर में सीएमओ पटल परिवर्तन के बाबत तेजी से चल रही थी।

अपरी कान्फाई के फेर में सीएमओ पटल परिवर्तन के बाबत तेजी से चल रही थी। उपरी कान्फाई के फेर में सीएमओ पटल परिवर्तन के बाबत तेजी से चल रही थी।

श्याम गुप्ता की जागीर नहीं है रामलीला भवन

नजूल भूमि पर बना रामलीला भवन किसी की बपौती नहीं, नगर पालिका का है

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। जिला मुख्यालय के पुरानी बाजार स्थित रामलीला भवन को लेकर श्याम गुप्ता पर ताम सवाल उठ खड़े हुए। जब रामलीला भवन श्याम गुप्ता का न कर्त्ता था और न है, तब श्याम गुप्ता को रामलीला से मोहे के पीछे भी ताम सवाल है। ऐसे में उसने कुछ हिन्दूवादी संगठनों को बरामद करीप्रदर्शन के समक्ष बदल रखा है। इस इमारत में रामलीला भवन का श्याम गुप्ता वाजार कर्त्ता को शर्तों पर दिया था। शर्तों में यह था कि बैनाम नजूल भूमि पर इमारत इस इमारत में रामलीला भवन को लेने का स्वामी का स्वामी के बिना कोई नया राज्यपाल/नोटीफाइड एविया/नार निर्माण नहीं हो सकता। मरम्मत के लिए भी मंजूरी जरूरी है। ऐसे में हक बनता है। नजूल भूमि पर बनी रामलीला की इमारत नगर पालिका अपने अधिकार में लेता है तो यह शर्तों के अनुकूल होगा।

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। रामलीला भवन को लेकर श्याम गुप्ता का न कर्त्ता था और न है, तब श्याम गुप्ता को रामलीला से मोहे के पीछे भी ताम सवाल है। ऐसे में उसने कुछ हिन्दूवादी संगठनों को बरामद करीप्रदर्शन के समक्ष बदल रखा है। इस इमारत में रामलीला भवन का श्याम गुप्ता वाजार कर्त्ता को शर्तों पर दिया था। शर्तों में यह था कि बैनाम नजूल भूमि पर इमारत इस इमारत में रामलीला भवन को लेने का स्वामी का स्वामी के बिना कोई नया राज्यपाल/नोटीफाइड एविया/नार निर्माण नहीं हो सकता। मरम्मत के लिए भी मंजूरी जरूरी है। ऐसे में हक बनता है। नजूल भूमि पर बनी रामलीला की इमारत नगर पालिका अपने अधिकार में लेता है तो यह शर्तों के अनुकूल होगा।

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। रामलीला भवन को लेकर श्याम गुप्ता का न कर्त्ता था और न है, तब श्याम गुप्ता को रामलीला से मोहे के पीछे भी ताम सवाल है। ऐसे में उसने कुछ हिन्दूवादी संगठनों को बरामद करीप्रदर्शन के समक्ष बदल रखा है। इस इमारत में रामलीला भवन का श्याम गुप्ता वाजार कर्त्ता को शर्तों पर दिया था। शर्तों में यह था कि बैनाम नजूल भूमि पर इमारत इस इमारत में रामलीला भवन को लेने का स्वामी का स्वामी के बिना कोई नया राज्यपाल/नोटीफाइड एविया/नार निर्माण नहीं हो सकता। मरम्मत के लिए भी मंजूरी जरूरी है। ऐसे में हक बनता है। नजूल भूमि पर बनी रामलीला की इमारत नगर पालिका अपने अधिकार में लेता है तो यह शर्तों के अनुकूल होगा।

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। रामलीला भवन को लेकर श्याम गुप्ता का न कर्त्ता था और न है, तब श्याम गुप्ता को रामलीला से मोहे के पीछे भी ताम सवाल है। ऐसे में उसने कुछ हिन्दूवादी संगठनों को बरामद करीप्रदर्शन के समक्ष बदल रखा है। इस इमारत में रामलीला भवन का श्याम गुप्ता वाजार कर्त्ता को शर्तों पर दिया था। शर्तों में यह था कि बैनाम नजूल भूमि पर इमारत इस इमारत में रामलीला भवन को लेने का स्वामी का स्वामी के बिना कोई नया राज्यपाल/नोटीफाइड एविया/नार निर्माण नहीं हो सकता। मरम्मत के लिए भी मंजूरी जरूरी है। ऐसे में हक बनता है। नजूल भूमि पर बनी रामलीला की इमारत नगर पालिका अपने अधिकार में लेता है तो यह शर्तों के अनुकूल होगा।

